



पुण्यस्मरण दिन



कालकथित गंगाबाई नागोराव बेंद्रीकर

के अठारहवें पुण्यस्मरण दिन के अवसर पर
नंदिग्राम टाइम्स परिवार की ओर से
विनम्र अभिवादन

केरल NEWS | केरल निकाय चुनाव परिणाम 2025

केरल निकाय चुनाव परिणाम 2025: तिरुवनंतपुरम में BJP की ऐतिहासिक जीत, PM मोदी ने दी अलग अंदाज में बधाई

नई दिल्ली | केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) को शिकस्त देते हुए सत्ता छीन ली है। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा, 'धन्यवाद तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा-राजग को मिला जनादेश केरल की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण है।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता को पूरा विश्वास है कि केरल की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है।



उन्होंने हैशटैग 'विकसित तिरुवनंतपुरम' के साथ कहा, 'हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास और लोगों के जीवन की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।' प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की ताकत हैं

आज का दिन केरल में पीढ़ियों से चले आ रहे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। हमारे कार्यकर्ता हमारी शक्ति हैं और हमें उन पर गर्व है!

पीएम मोदी ने केरल के लोगों का किया धन्यवाद केरल के उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। वे एनडीए को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं जो सुशासन प्रदान कर सकता है और सभी के लिए अवसरों से युक्त #विकासशीलकेरलम का निर्माण कर सकता है।

और सभी को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा, "भाजपा के सभी मेहनती कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लोगों के बीच जाकर काम किया।"

सीडीएस चौहान: रक्षा बल सुधारों और बदलते माहौल के अनुकूल



भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि युद्ध और सैन्य रणनीति में तेजी से बदलाव हो रहा है और भारतीय रक्षा बल इस बदलते वातावरण के अनुकूल बनने तथा आवश्यक सुधारों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बल हमेशा तत्पर और तैयार रह सके। उन्होंने डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में आयोजित 216 कोर्स कंबाईंड ग्रेजुएशन परेड में यह बात कही। जनरल चौहान ने कहा कि भारत की ताकत इसके मजबूत संस्थानों, लोकतांत्रिक स्थिरता और सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर आधारित है। उन्होंने यह भी बताया कि नए प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी ऐसे समय में सेवा में शामिल हो रहे हैं जब सशस्त्र बलों में एकीकृत संरचनाओं और संयुक्त संचालन को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भविष्य की सैन्य क्षमता को आकार दे रहे हैं।

कांग्रेस 'वोट चोरी' के मुद्दे पर रविवार को रामलीला मैदान में करेगी रैली, 50 हजार हस्ताक्षर जुटाने का किया दावा

नई दिल्ली: कांग्रेस रविवार को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करके 'वोट चोरी' के मुद्दे पर अपना अभियान तेज करेगी तथा सरकार और निर्वाचन आयोग को चुनाव में कथित तौर पर धांधली करने के लिए 'मिलीभगत' को लेकर कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सभा को संबोधित करने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट समेत शीर्ष नेता रैली में भाग लेंगे। सोनिया, राहुल समेत कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी रैली में मौजूद रहने की संभावना है। वरिष्ठ नेता पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में इकट्ठा होंगे और फिर बस से रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे।

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस रैली में लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था टाइट रखी गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। 'वोट चोरी' के खिलाफ लगभग 55 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी ने 'वोट चोरी' के खिलाफ लगभग 55 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। उन्होंने कहा कि 'राहुल जी ने सबूतों के साथ

दिखाया कि वोट चोरी कैसे हो रही है। उन्होंने गृह मंत्री को प्रेसवार्ता में उनसे बहस करने की चुनौती दी। लेकिन गृह मंत्री ने इसका भी जवाब नहीं दिया।" कांग्रेस 14 दिसंबर को **विशाल रैली** करेगी। रैली के बाद **राष्ट्रपति को 55 लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन** सौंपने की योजना है। यह कदम लोकसभा में **चुनाव सुधार और SIR मुद्दे** पर हुई हालिया बहस के बाद उठाया गया है।

थरूर ने केरल निकाय चुनाव में UDF और बीजेपी की जीत को बताया लोकतंत्र की सुंदर मिसाल



कांग्रेस नेता शशि थरूर ने निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में उन्होंने ट्विटर (X) पर लिखा कि केरल चुनावों के नतीजे स्पष्ट जनादेश और राज्य की लोकतांत्रिक भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने यूडीएफ के शानदार प्रदर्शन को 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संकेत बताया और कहा कि कड़ी मेहनत, स्पष्ट संदेश और सत्ता-विरोधी लहर ने 2020 की तुलना में बेहतर परिणाम दिए हैं। साथ ही थरूर ने

तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी के प्रदर्शन को राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव करार दिया और उसे भी बधाई दी, यह कहते हुए कि मतदाताओं ने बदलाव की मांग की। उनका बयान दोनों पार्टियों की जीत को लोकतांत्रिक विविधता और मतदाता इच्छा के सम्मान के रूप में दर्शाता है, जो राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को रेखांकित करता है।

लातूर: वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटील चाकूरकर को अंतिम विदाई, 'देवघर' से विशाल अंत्ययात्रा और राजकीय सम्मान



लातूर (महाराष्ट्र), 13 दिसंबर 2025: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर को शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बड़ी संख्या में राजनैतिक, सामाजिक और आम नागरिकों ने उनके 'देवघर' निवास से प्रारंभ हुई अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया, जो परंपरागत तौर पर वरवंटी गाँव के श्मशान घाट तक पहुंची। सुबह से ही पूरे लातूर शहर में शोक का माहौल रहा, और अधिकांश बाजार तथा व्यवसाय बंद रहे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पाटील चाकूरकर के निधन से प्रदेश और पार्टी दोनों में गहरा दुख व्याप्त है। हजारों नागरिक अंत्यदर्शन के लिए एकत्रित हुए, और रस्तों के दोनों ओर लोगों की भीड़ दिखाई दी।

शिवराज पाटील चाकूरकर नेतृत्व सदैव याद रखा जाएगा, तथा उनके योगदान ने पार्टी और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान की।

पाटील चाकूरकर का निधन 12 दिसंबर को उनके गृह नगर लातूर के 'देवघर' आवास पर एक लंबी बीमारी के बाद हुआ। वे 90 वर्ष के थे और उनके पीछे परिवार में उनका पुत्र शैलेश, सून डॉ. अर्चना और दो पोते-पोती शामिल हैं।

समाप्त सत्र और शोक सभा के दौरान राज्य भर के नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति ने एक सुसंस्कृत और सिद्ध साहचर्य वाले दिग्गज को खो दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भावुक शब्दों में कहा कि पाटील चाकूरकर का समर्पण और निष्कलंक

और अधिकांश बाजार तथा व्यवसाय बंद रहे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पाटील चाकूरकर के निधन से प्रदेश और पार्टी दोनों में गहरा दुख व्याप्त है। हजारों नागरिक अंत्यदर्शन के लिए एकत्रित हुए, और रस्तों के दोनों ओर लोगों की भीड़ दिखाई दी।

शिवराज पाटील चाकूरकर नेतृत्व सदैव याद रखा जाएगा, तथा उनके योगदान ने पार्टी और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान की।

पाटील चाकूरकर का निधन 12 दिसंबर को उनके गृह नगर लातूर के 'देवघर' आवास पर एक लंबी बीमारी के बाद हुआ। वे 90 वर्ष के थे और उनके पीछे परिवार में उनका पुत्र शैलेश, सून डॉ. अर्चना और दो पोते-पोती शामिल हैं।

समाप्त सत्र और शोक सभा के दौरान राज्य भर के नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति ने एक सुसंस्कृत और सिद्ध साहचर्य वाले दिग्गज को खो दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भावुक शब्दों में कहा कि पाटील चाकूरकर का समर्पण और निष्कलंक

परभणी जिल्हा सहकारी बँक: पदभरती व कर्ज वितरण में भारी अनियमितताएं, राज्य सहकार मंत्री ने महत्वपूर्ण जांच आदेश जारी किए

परभणी | 13 दिसंबर 2025: परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक में पदभरती प्रक्रियाओं तथा कर्ज वितरण में कथित रूप से भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील ने विस्तृत चौकशी (Inquiry) के आदेश जारी किए हैं। यह जानकारी विधानसभा के हिवाळी अधिवेशन के दौरान मिली।



राज्य सरकार के सहयोगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) के विधायक राजेश विटेकर ने विधानसभेत मंगलवार को जोरदार तर्क देते हुए बताया कि पिछले तीन से चार वर्षों में बैंक में भर्ती, जागीरदार नियुक्तियों और कर्ज वितरण में नियमों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हुआ है। उन्होंने कहा कि खासकर अनुकंपा के नाम पर असंगत भर्ती करके करीब 50 से 60 कर्मचारियों को नियोजित किया गया, जिनके पास सेवाओं के लिए वैध वारिस नहीं थे।

विटेकर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नियुक्तियों के लिए जिला शल्य चिकित्सक द्वारा जारी किए गए कथित फर्जी प्रमाणपत्रों का प्रयोग किया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया और भी संदिग्ध हो गई। इसके अलावा कई रोजगारी कर्मचारियों को नियमित सेवाओं में शामिल करने में भी अनियमितताएं देखने को मिलीं।

सरल सेवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान 152 जगहों के लिए कंपनी द्वारा बड़ी संख्या में आर्थिक लेनदेन किए जाने का आरोप भी लगाया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कर्ज वितरण में बैंक का दुरुपयोग हुआ, जहां मात्र मर्जी के संचालकों तथा उनके हितधारकों को बड़े पैमाने पर कर्ज दिए गए और कमीशन लेने जैसे गंभीर आरोप भी उठे हैं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा तत्व पर हुई कई नियुक्तियां अवैध पाई गई हैं, और उन सभी को रद्द कर दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि चौकसी में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि सहकार मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरल सेवा भर्ती प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है, और इसलिए सीधे तौर पर कंपनी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा, पर फिर भी पुणे स्थित सहकारी आयुक्त कार्यालय के अपर निबंधक इस जांच के नेतृत्व में नियुक्त होंगे।

बाळासाहेब पाटील ने आश्वासन दिया कि इस मामले की कसकर जांच (डिटेल इनक्वायरी) करने के लिए एक विशेष जांच समिति भी बनाई जाएगी और इसका ढांचा जल्द ही निर्धारित किया जाएगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इन अनियमितताओं का समय पर समाधान नहीं किया गया तो इससे न केवल बैंक कर्मचारियों की नियुक्तियों का भरोसा कमजोर होगा, बल्कि परभणी की सहकारी बैंक पर जनसामान्य का विश्वास भी प्रभावित हो सकता है।

राजनीतिक गतिरोध और विपक्ष का नेतृत्व: लोकतंत्र की अधूरी कड़ी

संपादकीय... |

महाराष्ट्र विधानमंडल का नागपुर में चल रहा हिवाळी अधिवेशन केवल विधायी कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस सत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मूलभूत आवश्यकता — विपक्ष के आधिकारिक नेतृत्व — का प्रश्न फिर से केंद्र में आ गया है। विपक्ष द्वारा दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) की नियुक्ति की मांग ने न केवल राजनीतिक बहस को तेज किया है, बल्कि सरकार की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विधानसभा और विधान परिषद में अब तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति न होना लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। उनका तर्क है कि विपक्ष का सशक्त और औपचारिक नेतृत्व न होने से सदन की कार्यप्रणाली असंतुलित हो जाती है और सरकार की जवाबदेही कमजोर पड़ती है।

भारतीय संसदीय प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होती। वह सरकार की नीतियों पर निगरानी, जनहित से जुड़े मुद्दों को मुखर रूप से उठाने और सत्ता-पक्ष को संवैधानिक दायरे में रखने का दायित्व निभाता है। यही कारण है कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को 'वॉचडॉग' कहा जाता है। महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में यह पद रिक्त रहना चिंता का विषय है।

विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस पद को रिक्त रखे हुए है, ताकि विपक्ष की संस्थागत ताकत को सीमित किया जा सके। सदन में प्रश्नकाल, चर्चा और समितियों के गठन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन की कार्यवाही कितनी प्रभावी और संतुलित रह सकती है?

सरकार की ओर से तर्क दिया जाता रहा है कि विपक्ष की संख्या या औपचारिक अर्हताओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। किंतु विपक्ष का कहना है कि यह मुद्दा तकनीकी से अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। पूर्व में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं, जब राजनीतिक सहमति से लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुचारु रूप से चलाया गया।

इस मुद्दे का असर केवल सदन के भीतर तक सीमित नहीं है। जनता से जुड़े सवाल — जैसे किसान संकट, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, महंगाई और क्षेत्रीय असंतुलन — प्रभावी ढंग से उठाने के लिए संगठित विपक्ष आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष का अभाव इन मुद्दों को हाशिये पर धकेल देता है, जिससे जनता की आवाज़ कमजोर पड़ती है।

हिवाळी अधिवेशन के दौरान विपक्ष ने यह भी मांग की कि विधानमंडल की कार्यवाही अधिक पारदर्शी, समावेशी और नियमसम्मत हो। उनका कहना है कि लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं चलता, बल्कि असहमति के सम्मान से चलता है। यदि विपक्ष को उसका संवैधानिक स्थान नहीं दिया जाएगा, तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के साथ समझौता होगा।

यह स्थिति केवल किसी एक दल या गठबंधन का प्रश्न नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक परंपरा और संसदीय गरिमा का सवाल है। राज्य की राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, किंतु लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखना सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी है।

अंततः यह आवश्यक है कि सरकार और सत्ता पक्ष राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर उठकर नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर गंभीरता से विचार करें। एक मजबूत विपक्ष न केवल सरकार के लिए चुनौती होता है, बल्कि बेहतर शासन का आधार भी बनता है।

लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने संवैधानिक दायित्वों का सम्मान करें। नागपुर का यह हिवाळी अधिवेशन यदि इस दिशा में कोई सकारात्मक संकेत देता है, तो यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।



Karnataka CM Fight: कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। डीके शिवकुमार को लेकर अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक ने तूफानी बयान दिया है। विधायक एच ए इकबाल हुसैन ने शनिवार को संभावना जताई है कि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार छह जनवरी को मुख्यमंत्री बनेंगे।

डीके शिवकुमार 6 जनवरी को बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक का दावा, कहा- सिद्धारमैया को पद खाली कर देना चाहिए

रामनगर (कर्नाटक): कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। डीके शिवकुमार को लेकर अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक ने तूफानी बयान दिया है। विधायक एच ए इकबाल हुसैन ने शनिवार को संभावना जताई है कि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार छह जनवरी को मुख्यमंत्री बनेंगे। रामनगर के विधायक हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का पद शिवकुमार के लिए खाली कर देना चाहिए और शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए।

विधायक एचए इकबाल हुसैन किसके समर्थक? शिवकुमार के कट्टर समर्थक माने जाने वाले विधायक एचए इकबाल

हुसैन कहा कि छह जनवरी को उनके (डीके शिवकुमार) मुख्यमंत्री बनने की 99 प्रतिशत संभावना है। जब उनसे पूछा गया कि इस तारीख का क्या महत्व है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। यह बस एक संख्या है। हर कोई यही कह रहा है। यह छह या नौ जनवरी हो सकती है। ये दो तारीखें हैं। हुसैन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। शुक्रवार को उन्होंने अपनी यह इच्छा जाहिर की थी।

मुख्यमंत्री पद के लिए गृह मंत्री जी परमेश्वर का समर्थन इस बीच रेल राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद वी सोमना ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए गृह मंत्री जी परमेश्वर का समर्थन कर रहे हैं।

सोमना ने तुमकुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि सत्ता मिलना भाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर सिर्फ गृह मंत्री बनकर रह जाएंगे। हम उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तुमकुरु के लोग भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।

शिवकुमार पर क्या बोले रेल राज्यमंत्री?

जब रेल राज्य मंत्री से किसी दर्शक ने मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शिवकुमार के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि छोड़िए इसे। यह गौण बात है। शिवकुमार क्या बनना चाहते हैं, यह उनके भाग्य पर निर्भर करता है। आचरण तो भाग्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

WORLD NEWS | अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं,

अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, F-16 अपग्रेड तो करेगा, पर नहीं देगा Link 22, ट्रंप को किस बात का डर

वॉशिंगटन/दुनिया — अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें अत्याधुनिक टैक्टिकल डेटा लिंक 'Link-22' शामिल नहीं होगा, जो उच्च-स्तरीय संचार क्षमता प्रदान करता है। यह निर्णय अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को 8 दिसंबर 2025 को भेजे गए एक औपचारिक नोटिफिकेशन के जरिए घोषित किया गया।

अमेरिका ने Pakistan Air Force के पुराने F-16 बेड़े के लिए लगभग \$989 मिलियन (करीब ₹8,500 करोड़) के अपग्रेड पैकेज को अनुमोदित किया है, जिसमें एवियोनिक्स सिस्टम, सुरक्षित संचार, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और प्रशिक्षण शामिल हैं। इस पैकेज का उद्देश्य इन विमानों को 2040 के दशक तक संचालन-योग्य बनाए रखना है।



इसके बावजूद, प्रस्ताव में Link-22 तकनीक शामिल नहीं है, जो आधुनिक नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध संचालन में अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित डेटा साझा करने का काम करती है। इस अपग्रेड के तहत पाकिस्तान को Link-16 डेटा लिंक सिस्टम दिए जाएंगे — यह NATO मानक पर आधारित है और मौजूदा

F-16 विमानों में पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है — लेकिन अधिक उन्नत Link-22 तकनीक से इन विमानों को संवेदनशील युद्ध क्षेत्र की जानकारी को व्यापक रूप से साझा करने में मदद मिलती, जो अब इस सौदे में नहीं है। विश्लेषकों के अनुसार इस फैसले के पीछे अमेरिका की सुरक्षा

चिंताएँ और भरोसे की कमी है, खासकर इस बात को लेकर कि अत्याधुनिक तकनीक किसी तीसरे देश, विशेषकर चीन तक पहुंच न पाए। Link-22 को अमेरिका आम तौर पर केवल अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों को उपलब्ध कराता है।

पाकिस्तानी वायुसेना के लिए यह अपग्रेड महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनके F-16 विमानों की सेवा-अवधि और कॉम्बैट रेडीनेस बढ़ेगी, मगर Link-22 के अभाव से उनकी नेटवर्क-संचालित सामरिक क्षमता सीमित रह सकती है।



Cricket News | IPL 2026 के ऑक्शन में किस देश से कितने खिलाड़ी?

IPL 2026 के ऑक्शन में किस देश से कितने खिलाड़ी? सबसे ज्यादा भारत तो सबसे कम प्लेयर्स इस देश के बिकेंगे



आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की सूची फाइनल हो गई है। इस बार 11 देशों के कुल 359 खिलाड़ी इस मिनी ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह नीलामी 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में होगी। कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब यह संख्या घटकर 359 रह गई है। इनमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी भारत से हैं, जिनकी संख्या 244 है। विदेशी खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी सबसे ज्यादा हैं।

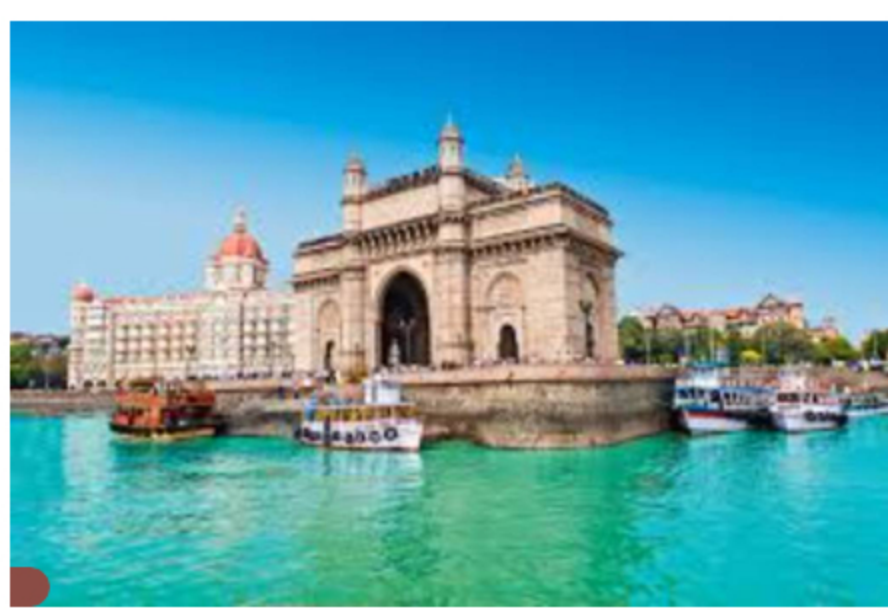
किस देश से कितने खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी सबसे ज्यादा संख्या में हैं। ऑस्ट्रेलिया से 21 खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे, जबकि इंग्लैंड से

22 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह इन दोनों देशों के लिए एक बड़ी संख्या है। अन्य देशों से भी खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है। आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोश लिटिल अपने देश के अकेले खिलाड़ी हैं जो इस नीलामी में शामिल होंगे। वहीं, मलेशिया के वीरनदीप सिंह को भी अंतिम शॉर्टलिस्ट में जगह मिली है। यह दिखाता है कि आईपीएल अब सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनियाभर के खिलाड़ियों को मौका दे रहा है।

नीलामी के लिए देशों के हिसाब से खिलाड़ियों का वितरण इस प्रकार है: *भारत: 244 खिलाड़ी *अफगानिस्तान: 10 खिलाड़ी *बांग्लादेश: 7 खिलाड़ी

*इंग्लैंड: 22 खिलाड़ी *आयरलैंड: 1 खिलाड़ी *मलेशिया: 1 खिलाड़ी *न्यूजीलैंड: 16 खिलाड़ी *दक्षिण अफ्रीका: 16 खिलाड़ी *श्रीलंका: 12 खिलाड़ी *वेस्टइंडीज: 9 खिलाड़ी *ऑस्ट्रेलिया: 21 खिलाड़ी

कई देश के खिलाड़ियों का दबदबा यह सूची दर्शाती है कि भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो है ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों से भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी नीलामी में आ रहे हैं। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से भी 16-16 खिलाड़ी शामिल हैं, जो इन देशों की क्रिकेट प्रतिभा को दिखाता है। श्रीलंका से 12 और वेस्टइंडीज से 9 खिलाड़ी नीलामी में अपनी जगह बनाएंगे।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Sunday 14th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 228 , पृष्ठ 03



नागपुर: प्रदर्शन के दौरान महिला शिक्षिका की तबियत बिगड़ी, विधान भवन के बाहर तनावपूर्ण माहौल

नागपुर: महाराष्ट्र अधिकारिक माँगों को लेकर अन्नत्याग आंदोलन चला रही है। आंदोलन के दौरान महिला शिक्षिका अचानक बदलती स्वास्थ्य स्थिति के कारण गिर पड़ी। मौके पर मौजूद साथी कार्यकर्ताओं ने तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। प्रदर्शन स्थल पर तनाव का स्तर बढ़ता चला गया, लेकिन पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच किसी बड़ी झड़प की खबर अभी तक सामने नहीं आई है।

नागपुर: महाराष्ट्र अधिकारिक माँगों को लेकर अन्नत्याग आंदोलन चला रही है। आंदोलन के दौरान महिला शिक्षिका अचानक बदलती स्वास्थ्य स्थिति के कारण गिर पड़ी। मौके पर मौजूद साथी कार्यकर्ताओं ने तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। प्रदर्शन स्थल पर तनाव का स्तर बढ़ता चला गया, लेकिन पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच किसी बड़ी झड़प की खबर अभी तक सामने नहीं आई है।

शिक्षण संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से नियमित वेतन और सेवा से जुड़ी

नवी मुंबई | में सिडको घरों की कीमतों में 10% की ऐतिहासिक कटौती की घोषणा

नवी मुंबई में सिडको घरों की कीमतों में 10% की ऐतिहासिक कटौती की घोषणा — घर खरीदने का सपना होगा सस्ता और साकार

NEWS AGENCY

नागपुर: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधान परिषद में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए नवी मुंबई के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) द्वारा बनाए जा रहे घरों की कीमतों में प्रतिशत 10 की बड़ी कटौती करने का निर्णय किया है। इस कदम को विशेषज्ञों और आम जनता दोनों ने ऐतिहासिक और राहतभरा निर्णय बताया है।



सरकार के इस निर्णय के तहत नवी मुंबई के विभिन्न आवासीय प्रकल्पों में शामिल सिडको घरों की कीमतें 10% तक कम कर दी जाएंगी। इससे विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने में आर्थिक

राहत मिलने की उम्मीद है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिडको द्वारा पहले से निर्धारित दरों में यह कटौती आम जनता के घर खरीदने के सपने को साकार करने के उद्देश्य से की जा रही है। नवी मुंबई जैसे विकसित

शहर में यह निर्णय घर खरीदने वालों के लिए और अधिक अवसर प्रदान करेगा। सूत्रों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत खारघर, वाशी, तळोजा, उलवे, पनवेल और कळंबोली जैसे प्रमुख इलाकों में प्रस्तावित लगभग 17,000 घरों के लिए लॉटरी प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की संभावना है। इन घरों की कीमतों में 10% की कटौती से उनका खरीद मूल्य पहले से काफी सस्ता हो जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न सिर्फ आम नागरिकों को सस्ते आवास उपलब्ध होंगे, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे घरों की मांग बढ़ेगी और परियोजनाओं में निवेश को मजबूती मिलेगी।

सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब गृहस्वामित्व को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण मकसद है, और इससे कई परिवारों के लिए घर खरीदने का लंबे समय से चला आ रहा सपना सच होने की उम्मीद जगी है।



मराठवाड़ा: हैदराबाद गैज़ेटियर के आधार पर तीन महीने में केवल 98 कुणबी प्रमाणपत्र जारी — सरकार पर नाराज़गी

जालना | मराठा आरक्षण से जुड़ी हैदराबाद गैज़ेटियर (Hyderabad Gazetteer) के कार्यान्वयन के तीन महीनों के भीतर मराठवाड़ा क्षेत्र में केवल 98 कुणबी जाति प्रमाणपत्र वितरित किए गए हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होने पर मराठा नेताओं ने राज्य सरकार की दुर्बल भूमिका पर तीखी आलोचना की है।



मराठा आरक्षण के संघर्षोद्धा मनोज जरांगे पाटील ने शुक्रवार को बताया कि 2 सितंबर को जारी सरकारी निर्णय (GR) के बावजूद मराठवाड़ा के आठ जिलों में 594 आवेदन दाखिल होने के बाद भी सिर्फ 98 प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

इस धीमी प्रक्रिया पर उन्होंने सरकार को फसवणूक (धोखा) करने का आरोप लगाया है। जरांगे ने कहा कि संभाजीनगर (औरंगाबाद) में तो अब तक कोई भी प्रमाणपत्र वितरित नहीं किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी स्वीकृत प्रमाणपत्रों की

संख्या अपेक्षाकृत बेहद कम है। अधिकारियों ने प्रमाणपत्र जारी करने में आदेशों के अभाव को कारण बताया है।

मनोज जरांगे ने मांग की है कि गांव-गांव तक समितियाँ गठित कर विशेष अभियान चलाया जाए,

ताकि योग्य मराठा समाज के लोगों को शीघ्रता से कुणबी प्रमाणपत्र मिल सकें और वे आरक्षण के लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण मराठा समाज में नाराज़गी बढ़ रही है। इससे पहले सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हैदराबाद गैज़ेटियर के अभिलेखों को कुणबी प्रमाणपत्र के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया था, जिससे योग्य लोगों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन आवेदन बढ़ने के बावजूद प्रमाणपत्र जारी करने की गति सुस्त होने के कारण आंदोलनकारियों में असंतोष बढ़ गया है।

हिंगोली: पोत्रा इलाके में दूसरी बार तेंदुए का हमला, ग्रामीणों का दावा — तीन तेंदुए सक्रिय, वन विभाग पर निष्क्रियता के आरोप

हिंगोली, 13 दिसंबर 2025 — कळमनूरी तहसील के पोत्रा और आसपास के ग्राम क्षेत्रों में तेंदुए के लगातार हमलों से दहशत का माहौल बना हुआ है। दूसरे एक ही हफ्ते में तेंदुए ने ग्रामीण पशुधन को निशाना बनाया, जिससे स्थानीय जनता में भय और असुरक्षा की स्थिति बन गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, पिछले पंद्रह दिनों से पोत्रा, तेलंगवाडी, टक्हा, जांब और कवडा क्षेत्रों में तेंदुए का वर्चस्व देखा जा रहा है। दो दिन पहले तेलंगवाडी में बकरी का शिकार करने के बाद, 12 दिसंबर की सुबह तेंदुए ने पोत्रा के गजानन पतंगे के खेत में दो वर्ष की एक वासर (गाय के छोटे बच्चे) को शिकार कर लिया, और उसकी अधिकांश लाश को खा लिया। इसके कारण आसपास के खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने काम बंद कर दिया है और ग्रामीणों में भय की स्थिति है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पोत्रा और तेलंगवाडी इलाकों में केवल एक नहीं बल्कि तीन तेंदुए घूम रहे हैं — एक वयस्क तेंदुआ और दो उसके पिल्ले — जो अक्सर ग्रामीण इलाकों के नजदीक शिकार की तलाश में आते हुए देखे गए हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की प्रतिक्रिया न तो पर्याप्त है

और न ही समय पर प्रभावी। अधिकारी केवल क्षेत्र में डोंबरी रास्तों पर निरीक्षण कर लौट जाते हैं और ग्रामीणों को “डोल-ढमाके करें” व “समूह में घूमने” जैसे सामान्य सुझाव देकर स्थिति का समाधान नहीं कर पा रहे हैं।

कुछ युवकों द्वारा तेंदुए का वीडियो भी बनाया गया था जिसमें वह खलचा तुरी के पास घूमता दिखाई देता है, लेकिन वन विभाग ने इस वीडियो को “ए.आई. तकनीक से निर्मित” बताकर उसकी प्रामाणिकता से इनकार कर दिया, जिससे ग्रामीण और आक्रोशित हो गए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि अगर तेंदुए द्वारा किसी इंसान पर हमला होता है और कोई गंभीर चोट या मौत होती है, तो वे वन विभाग के निष्क्रिय निर्णयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को बाध्य होंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से लोगों की जान खतरे में पड़ेगी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग अब तक तल्लाशी और निगरानी बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग तुरंत तेंदुए को पकड़ने व सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में और अधिक नुकसान रोका जा सके।



नागपुर / 13 दिसंबर 2025: केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी अवसंरचना घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवहन नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुंबई और पुणे के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा,

मुंबई-पुणे का सफर अब डेढ़ घंटे में संभव! नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में नए एक्सप्रेसवे निर्माण की घोषणा की

जिससे दोनों शहरों के बीच आवागमन का समय केवल डेढ़ (1.5) घंटे तक घट जाएगा।

गडकरी ने यह घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की, जहां उन्होंने बताया कि राज्य के लिए कुल 1.50 लाख करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इस व्यापक योजना के तहत मुंबई-पुणे के मौजूदा मार्ग के समानांतर एक नया एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये रखी गई है। इसका उद्देश्य दोनों महानगरों के बीच यात्रा समय और दूरी को काफी कम करना है। उन्होंने बताया कि नया एक्सप्रेसवे न केवल

मुंबई-पुणे की दूरी 90 मिनट में पूरी करने में सहायक होगा, बल्कि मुंबई, पुणे और बेंगलुरु के बीच यात्रा समय को भी लगभग 5.5 घंटे तक घटाने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह नई सड़क प्रणाली राज्य में यातायात के दबाव को भी काफी हद तक कम करेगी।

गडकरी ने यह भी कहा कि पुणे क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये के सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है, और यह कार्य अगले तीन महीनों के भीतर शुरू किया जाएगा। साथ ही तलेगांव-चकन-शिकरापुर एलिवेटेड सड़क परियोजना जैसी योजनाओं की आधारशिला स्थानीय निकाय चुनावों के बाद रखी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सड़क परियोजनाएं वर्ष 2026 से धरातल पर उतरेंगी, और इनके माध्यम से महाराष्ट्र में लोगों की दैनिक यात्रा अधिक आसान, तेज़ और सुरक्षित बनेगी। साथ ही, इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण न केवल यात्रा समय को कम करेगा, बल्कि आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इससे व्यापारिक क्षेत्रों की संपर्क सुविधा बढ़ेगी और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।



